

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून दिनांक 09 मार्च, 2017

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 506/
एस0एस0/2016 शकुन्तला मार्टन जू0हा0स्कूल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य
में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.जनवरी, 2017 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-विधि-10(1)/24396/2016-17 दिनांक 27 जनवरी, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अन्तरिम आदेश दिनांक 10. जनवरी, 2017 पारित किया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा स्टे वैकेट एप्लीकेशन दाखिल किया जा चुका है। अतः मा0 उच्च न्यायालय की नियमावली के अध्याय-5 नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी अन्तरिम आदेश के खिलाफ विशेष अपील मान्य नहीं है।

अतः इस संबंध में सम्यक विचारोंपरान्त शकुन्तला मार्टन जू0हा0स्कूल सिविल लाईन जनपद पौड़ी गढ़वाल को अनुदान सूची से पृथक किये जाने (निरस्त) किये जाने विषयक कार्यालय आदेश संख्या-1775/XXIV-4-6(10)/2014 दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किये जाने के मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05 मार्च 2016 एवं आदेश दिनांक 10 जनवरी 2017 के अनुपालन में संबंधित शासनादेश संख्या-204/14-XXIV-4-6(10)/2014 दिनांक 04 मार्च, 2014 के क्रम में नियमानुसार वेतन अनुदान तत्काल प्रभाव से अवमुक्त किया जाय।

2. उक्त कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-506/एस0एस0/2016 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा, एवं उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिये जाने की स्थिति में उक्त विद्यालय को दिया गया वेतन अनुदान तत्काल वापस किया जाना होगा।

भवदीय,

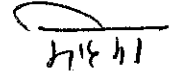
(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

संख्या- 171/xxiv-4/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
- 3- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत मामले में विभागीय नियमों एवं मानकों के आलोक में तथ्यपरक प्रमाणिक सूचनाओं के साथ विभागीय पक्ष प्रस्तुत करते हुए किसी भिन्न अधिकारी के माध्यम से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 5- सभापति विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
- 6- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 7- कोषाधिकारी, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 8- मण्डलीय अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 9- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- संबन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(महिमा)

उप सचिव।